जनगर्जन

वर्ष 24 अंक 10 मासिक नई दिल्ली जून 2010 विक्रमी संवत्-2067 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

फारवर्ड ब्लॉक स्थापना दिवस - आज भी प्रासंगिक

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

22 जनू प्रति वर्ष आता है और हमें उन सपनों की याद दिलाता है जो पूरा होना अभी बाकि है। सुभाष चन्द्र बोस ने एक आजाद और खुशहाल भारत का सपना देखा था तथा जिसे प्राप्त करने के लिये व्यापक संघर्ष को दो चरणों में विभाजित किया था। 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तिफा दे दिया तथा उसके तुरन्त बाद ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत की आजादी के लिये सभी मोर्चो पर समझौता विहीन संघर्ष के लिये अपनी एक पार्टी 'फारवर्ड ब्लॉक' बनाई। यह उनके संघर्ष का प्रथम चरण था। आजाद एवं खुशहाल भारत के लिये सुदृढ़ एवं व्यापक संघर्ष के साथ-साथ देश में समाजवाद की स्थापना के सपनें को साकार करने के लिये दूरगामी एवं व्यापक योजना तैयार की। लेकिन हमारी आजादी के 63 वर्ष बाद भी, उनके सपनें का समाजवादी व्यवस्था कायम करने से काफी दूर है। हमारे संविधान में एकमात्र संशोधन से, भारत को समाजवादी राज्य घोषित कर दिया गया, लेकिन देश में समाजवाद का तिलमात्र लक्ष्ण भी नहीं है हमारे देश में भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि के अलावा अन्य मानवीय आवश्यकताओं की काफी भिन्नता है। हमारा समाज दो भागों में विभाजित 'अमीर' एवं 'गरीब', और जाहिर तौर गरीबों की संख्या हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती ही जा रही है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि, आज हमारे देश में सामाजिक - आर्थिक नीति इस प्रकार तैयार की जा रही है कि अमीर और अधिक अमीर हो रहे है एवं गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। एक ओर जहाँ देश में गरीबी और भूखमरी से लदी हुई है वहीं दूसरी ओर समाज के हर क्षेत्र में प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व व्यापक रूप से लूट-खसोट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सम्प्रदायवाद और जातिवाद देश की एकता को खतरा पहुँचा रहे हैं। देश में समाजवाद की स्थापना के लिये इस मनहूस आर्थिक-सामाजिक स्थिति से हमें एकजुट होकर लड़ने की अविलम्ब आवश्यकता है। 22 जून अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना दिवस हमारे इस अधूरे कार्य को पूरा करने की मांग करता है।

नेताजी ने अपने पूरे जीवन के संघर्ष और और वैचारिक गतिविधियों से हमें समाजवाद का मार्ग दर्शाया था। आजादी के संघर्ष के उन व्यस्त दिनों के दौरान, भारत एवं भारत के बाहर, नेताजी ने अपने देशवासियों को देशभक्ति सिखाया जो नये भारत के निर्माण के लिये एक शक्ति बन सकता था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने देशभक्ति का मात्र पाठ नहीं पढ़ाया, बल्कि उन्होंने उसके साथ-साथ अपने जीवन को देशभक्ति के मार्ग और कार्य में झोंक दिया। इस प्रकार समाजवाद की स्थापना के संघर्ष के लिये उन्होंने अपने अनुयायियों के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एकमात्र वह ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो देश में - 'एकता', 'विश्वास' और 'बलिदान' के उद्देश्य के लिये लोगों को पूकार सकते हैं। नेताजी के नेतृत्व में बहादुर आजाद हिन्द फौज पूर्ण रूप से अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी और एकजुटता का उदाहरण प्रस्तुत करती थी - चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हो - वे सभी देश के लिये लड़ते थे। आजाद हिन्द फौज के सिपाही अपने सबसे बड़े मुखिया नेताजी सुभाष चन्द्र बोस में पूर्ण आस्था रखते थे एवं उनके आदर्शों और योजनाओं में अपनी अंतरआत्मा से विश्वास करते थे। इस विश्वास और आदर्श को दिल से मानते हुये, 'दिल्ली चलो' मार्च के दौरान एंग्लो-अमेरिकी साम्राज्यवादीयों के साथ लड़ते हुये कईयों ने अपनी जान न्यौछावर कर दिया। नेताजी के सपनों का समाजवादी भारत के निर्माण के उद्देश्य के लिये आज प्रत्येक भारतीय को ईमानदारी के साथ उनकी योजनाओं का पालन करना चाहिये।

1931 में ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में नेताजी ने कहा था - 'मुझे भारत की आजादी के संदर्भ में क्षणिक भी शंका नहीं है, जो पूरे विश्व में, समाजवाद का उदाहरण होगा'। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना दिवस 22 जून नेताजी का भारत एक समाजवादी भारत की स्थापना की मांग करता हैं।

26 साल पुराना भोपाल गैस त्रासदी: कम्पनी परस्त केन्द्र व राज्य सरकार का सच सामने आया

भोपाल में 1984 की सर्द रातें यूनियन कार्बाइड की कैमिकल फैक्टरी में दुनियां की सबसे बड़ी जहरीली गैस रिसाव का गवाह बना था, जिसके कारण घटना के समय ही दो घंटे के अंदर ही 10,000 लोगों की जान चली गई थी। एक महीने के भीतर ही हताहतों की संख्या 20,000 आंकड़े के पार चली गयी थी, आने वाली नई पीढ़ी के बच्चों को पंगु बना दिया था। कांग्रेस की केन्द्र और राज्य सरकार के कठोर रवैये के कारण गरीबों के नुकसान का मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था आज तक न देकर उनके दु:खों को और भी गहरा कर दिया। इसके अलावा, इस अभूतपूर्व गैस त्रासदी पर 26 साल बीत जाने के बाद जिला न्यायालय द्वारा सुनाये गये फैसले ने पीड़ितों के घावों को और गहरा दिया तथा न्याय की ऐसी प्रक्रिया पर एक प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देता है।

हाल में आये जिला न्यायालय क फैसले के अनुसार, क्षेत्रीय यूनियन कार्बाइड के 8 प्रबंधकों को मात्र दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई, और फैसले के दो घंटे में ही जमानत भी दे दी। यूनियन कार्बाइड कम्पनी के मुखिया वारेन एंडरसन को इस फैसले में पूरी तरह से अनदेखा किया गया तथा वह अमेरिका में सुरक्षित रूप से आवास कर रहा है। 26 वर्षों के बाद आये इस प्रकार के न्यायिक फैसले ने गैस त्रासदी के जुड़े विवाद एक बाद फिर सामने आ गये है।

यह बिल्कुल अजीब लगता है कि जब इस आपदा पर न्यायायिक फैसले में कम से कम सजा सुनाई गई तब राजनैतिक विवादों ने जोर पकड़ लिया जबकि संसार की औद्योगिक विपदा जब 1984 में घटित हुई थी उस समय राजनैतिक विवाद बहुत कम थी। मध्य प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह पर एक प्रश्न यहाँ उठता है, जिन्होंने सक्रिय रूप से एंडरसन को देश छोड़ने में सुविधा मुहैया कराया। लेकिन एक मुद्दा यह भी है कि इस प्रकार से देश से भागने की सूचना उस समय के कांग्रेसी प्रधान मंत्री राजीव गांधी की जानकारी के बिना संभव नहीं हो सकती। जब यहाँ गैस त्रासदी के शिकार हजारों भारतीय अपने दु:खों से पीड़ित थे, उस समय कांग्रेस के नेता इस औद्योगिक घराने के दोषी अमेरिकी मुखिया को बचाने के घृणित कार्य में लगे हुये थे। इसके अलावा अगली उंगली पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार पर जाती है, 1994-1995 में एंडरसन को भारत लाकर उचित जाँच के लिये सीबीआई की दलील को उनके विदेश विभाग ने आपत्ति जताई थी। न्याय की खातिर, हम मांग करते हैं कि भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका से एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिये अविलम्ब बात करें और पूरे गैर त्रासदी पर सीबीई द्वारा नये शिरे से जाँच प्रक्रिया आरम्भ करें। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जैसा कि कहा था कि अमेरिकी कंपनी डाउ कैमिकल, जिसने यूनियन कार्बाइड को अपने हाथ में ले लिया था, भी इसके लिये जिम्मेदार है और वह पूरे मुआवजे की अदायगी करे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 470 मिलियन डॉलर का मुआवजा कम है तथा इस पर बार पुन: विचार किया जाना चाहिये।

वास्तव में, विभिन्न तथ्यों और साक्ष्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि, न्यायिक प्रक्रिया तथा दंड और मुआवजा आदि जाँच के संबंध में जानबुझकर अनदेखा किया गया। और सबसे नुकसान में भोपाल गैस काण्ड के हजारों पीड़ित रहे। हमें यह देखना चाहिये कि इतने देर से आया फैसला उन्हें न्याय दिला सका ?हाल ही में प्रस्तावित नागरिक परमाणु क्षति उत्तरदायित्व विधेयक 2010 ने भोपाल गैस त्रासदी के विवाद को ईंधन का कार्य कर रही है। सत्तारूढ़ पार्टी और स्थानीय तथा विदेशी कारपोरेट घरानों के बढ़ते संबंधों समय-समय पर उजागर होती रहती है। जनता को इससे पूरी तरह सचेत रहने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करना वामदलों का उत्तरदायित्व है। अत: भोपाल गैस त्रासदी पर नये सिरे से सीबीआई जाँच की मांग करते हैं और अपराधियों को सजा दी जाये तथा गरीब पीड़ितों को मुआवजा एवं न्याय मिल सके।

फारवर्ड ब्लॉक के उपाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) अमर सिंह कुशवाहा का निधन

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी के उपाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) अमर सिंह कुशवाहा जी का निधन 65 वर्ष की आयु में कानपुर में 11 जून 2010 को हो गया।

मस्तिष्क स्राव के कारण प्रो. कुशवाहा जी पिछले महीने कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे।

वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सच्चे अनुयायी थे और उत्तर प्रदेश में वाम-लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। उन्होंने भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को संगठित करने के लिये उल्लेखनीय योगदान दिया। वे कई बार

कानपुर विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष चयनित किये गये और वे एआईएफसीयूटीए के प्रमुख कार्यकर्ता थे।

1978 में वे अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के यूवा नेता के रूप में सदस्य बने और वे ऑल इण्डिया यूथ लीग के अध्यक्ष और महासचिव भी रहे। वे लम्बे समय तक अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव भी चयनित हुये एवं 2005 में फारवर्ड ब्लॉक के धनबाद सम्मेलन में पहली बार पार्टी के उपाध्यक्ष चुने गये, तत्पश्चात् 2009 में कोलकाता सम्मेलन में वे दुबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधि के रूप में कई देशों का भी भ्रमण किया था।

वे एक अच्छे वक्ता भी थे तथा पार्टी की हिन्दी पत्रिका 'जनगर्जन' के सदस्य भी थे।

केन्द्रीय कमिटी प्रो. अमर सिंह कुशवाहा के दुःखद एवं आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने अपने केन्द्रीय नेतृत्व में से एक दिग्गज नेता को खो दिया। उनके निधन से सिर्फ अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक को ही नहीं अपितु देश की वाम आन्दोलन को भी धक्का लगा है।

पार्टी ने एक सप्ताह का शोक मनाया।

प्रो. अमर सिंह कुशवाहा का निधन उत्तर प्रदेश की वाम आंदोलन को गहरा धक्का

कानपुर 27 जून : आजाद नगर के सरयू नारायण बाल विद्यालय में 27 जून को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं शिक्षक आन्दोलन के प्रणेता स्व० प्रो॰ अमर सिंह कुशवाहा की शोक सभा आयोजित की गयी। शोक सभा में सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी सहित कई राजनैतिक नेताओं के साथ-साथ विभिन्न समाजसेवी संगठनों एवं स्कूलों व कॉलेजों के अध्यापकगणों ने भाग लिया।

साथी देवब्रत बिश्वास ने कुशवाहा जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक सभा संचालित किया। साथी बिश्वास जी ने बताया कि कुशवाहा जी वे 21 मई 2010 को रतनदीप अस्पताल में मुलाकात की थी, जहाँ वे आई.सी.यू. में भर्ती थे, वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सच्चे अनुयायी थे, तथा उनके निधन से उत्तर प्रदेश की वाम आंदोलन को गहरा आघात पहुँचा है। कुशवाहा जी शिक्षक आन्दोलन के साथ-साथ छात्र और नौजवानों के आन्दोलनों से भी जुड़े रहे।

उनके कार्यो एवं बलिदानों को उपस्थित नेताओं एवं अध्यापकों ने भी सराहा। कानपुर विश्वविद्यालय अध्यक्ष ने कहा कि कुशवाहा के निधन से शिक्षक आंदोलन को काफी गहरा आघात लगा है, जिसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। सभा में फारवर्ड ब्लॉक उत्तर प्रदेश इकाई महासचिव साथी एस.एन. सिंह कुशवाहा, यूथ लीग महासचिव साथी संजय भट्टाचार्य, ट्रेड यूनियन नेता साथी हंसराज अकेला, साथी अनिल शर्मा (बिहार), साथी संजय यादव (मध्य प्रदेश) आदि भी उपस्थित थे।

कानपुर की जनता एवं उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुशवाहा जी इच्छानुसार कानपुर शहर में ऑल इण्डिया स्टुडेन्ट्स ब्लॉक का राष्ट्रीय सम्मेलन कराने का अधूरा कार्य हम सभी मिलकर पूरा करेंगे।

त्रासदीपूर्ण न्याय ...!

जयन्त वर्मा

लगभग 25 हजार लोगों की जान लेने वाली दुनियां की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के 26 साल बाद भोपाल की अदालत ने यूनियन कार्बाइड कम्पनी के आठ अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, जिसमें कम्पनी के चेयरमैन वारेन एण्डरसन को सजा से मुक्त रखां इस फैसले पर आश्चर्य करते हुये विश्वव्यापी प्रतिक्रिया आ रही है। अनेक तथ्य उजागर हो रहे हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को कम किया तथा तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति ए.एम. अहमदी रिटायरमेन्ट के बाद भी बी.एम.एच.टी. के आजीवन चेयरमैन बना दिए गये। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने घटना के तत्काल बाद भोपाल में गिरफ्तार किए गए कम्पनी के चेयरमैन वारेन एण्डरसन को सरकारी विमान से दिल्ली भिजवाया और शीघ्र ही वह अमेरिका लौट गया।

इस प्रकरण ने हमारे देश की राज्य - व्यवस्था को नंगा कर दिया है। यह साफ हो गया है कि भारत में वास्तविक रूप से बड़े कार्पोरेट घरानों का राज चल

रहा है तथा राजनेता उनके मोहरों की तरह करम करते हैं। जस्टिस अहमदी के अनुसार भारत में इस प्रकार के गंभीर हादसों के लिए दोष सिद्ध करने और उन्हें सजा देने बाबत कारगर कानून ही नहीं है।

भारत के संविधान में न्यायाधीशों के शपथ का जो प्रारूप दिया गया है वह स्पष्ट करता है कि न्यायाधीशों का कार्य न्याय देना नहीं बल्कि संविधान और कानूनों की मर्यादा बना कर रखने का है। मंत्रियों के लिए निर्धारित शपथ में लोगों के प्रति न्याय करने का उल्लेख है। यदि कानून ही अन्यायकारी होगा तो न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करना निरर्थक है।

आजादी के पूर्व अँग्रेजी हुकूमत ने सैकड़ों कानूनों के जरिये भारत की जनता को गुलाम बनाया था। आजादी के 60 वर्ष बाद आज भी ब्रिटिश हुकूमत के लगभग 350 कानून प्रभावशाली हैं। अपराध क्या है यह ब्रिटिश हुकूमत ने परिभाषित किया था। उसी परिभाषा से 25 हजार लोगों के हत्यारों को मात्र 2 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकी है। व्यक्ति के विरुद्ध अपराध तो अपराध थे किन्तु समाज के विरुद्ध अपराधों की अनदेखी की गई क्योंकि स्वयं ब्रिटिश हुकूमत भारतीय समाज के विरुद्ध अपराध कर रही थी। आजादी के बाद भारत की विधायिका, संसद और विधानसभाओं ने इस संबंध में कोई विचार नहीं किया। कदाचित इसलिए कि राजनेताओं का बहुमत भी उसी नीयत से शासन कर रहा है, जिससे ब्रिटिश हुकूमत को जनता का गुलाम बनाकर रखा था।

मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कानून में प्राणघातक पदार्थों को नगर निगम सीमा के भीतर संग्रहित करने पर प्रतिबंध है। सभी को ज्ञात था कि मीथाइल आइसोसाइनेट से यूनियन कार्बाइड संयंत्र में कीटनाशक बनता है। यह संयंत्र म्यूनिसिपल सीमा के भीतर अवैध रूप से चल रहा था। इसी प्रकार भोपाल का मास्टर प्लान 1975 में बना था, जिसमें कीटनाशक फैक्टरी को घातक संयंत्रों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी फैक्टरी लीवार्ड दिशा (हवा के रूख के अंतिम छोर पर) में अर्थात् खेजड़ा बरामद ग्राम में स्थापित करने का प्रावधान था। 1984 क उक्त फैक्टरी मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए चलती रही। यह सब इसीलिए चलता रहा कि बड़े कार्पोरेट घराने सरकार से ऊपर हैं। म्यूनिसिपल कानून और टाउन प्लानिंग कानूनों का उपयोग कर गरीबों के झोपड़ें उजाड़ने में सरकार तत्परता दिखाती है किन्तु यूनियन कार्बाइड को छूट दी जाती है।

यह तथ्य भी उजागर हुआ कि कि अर्जुन सिंह के परिवार द्वारा संचालित चुरहट बाल-कल्याण सोसायटी को यूनियन कार्बाइड से करोड़ों रुपये दान के रूप में मिले थे। वास्तव में यह दान रिश्वत के रूप में दिया गया था और ऐसी रिश्वत नंबर एक या नंबर दो में लेकर हमारे राजनेता बड़े कार्पोरेट घरानों की चाकरी करते रहते हैं। दुष्परिणाम सामान्यजन को भुगतना पड़ता हैं क्योंकि अन्यायपूर्ण कानूनों के आधार पर न्याय (?) होता रहता है, जिसका उदाहरण गैस त्रासदी पर आए फैसले के रूप में हम देख रहे हैं।

फारवर्ड ब्लॉक का प्रोग्राम

(8 मई 1939 को हावड़ा में साधारण आम सभा में तथा 18 मई 1930 को पत्रकारों के साथ हुई चर्चा का सारांश)

फारवर्ड ब्लॉक के दो लक्ष्य है - पहला सुधारवादी तथा उदारवादी विचार वालों के बजाय क्रान्तिकारी विचार धारा वालों के साथ कांग्रेस के वर्तमान कार्यक्रमों के लिए काम करना। दूसरा फारवर्ड ब्लॉक का अपना जो कार्यक्रम है उसके लिए ऐसे काम करना ताकि कांग्रेस स्वीकार कर ले इसके लिए कांग्रेस पर दबाव बनाना। फारवर्ड ब्लॉक का यह अग्रगामी कार्यक्रम भारत की पूर्ण आजादी जल्द से जल्द प्राप्त करना है।

फारवर्ड ब्लॉक तमाम साम्राज्यवाद विरोधी, क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील समुहों का जिसमें सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल है एक मंच होने के कारण कांग्रेस में मौजूद वामपंथी पार्टियों तथा समूहों के प्रति स्वाभाविक रूप में दोस्ताना रूख रखेगा। फारवर्ड ब्लॉक जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे वे कमजोर हो। फारवर्ड ब्लॉक को आशा है कि उन पार्टियों या समूहों के साथी फारवर्ड ब्लॉक के सदस्य बनेंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ समय से हम संवैधानिकता की ओर बराबर झुकते जा रहे हैं। यह झुकाव जबसे कई प्रांतों में कांग्रेस जनो ने मिनिस्टरशिप संभाली है, विशेष रूप से बढ़ा है। नई पनपी पार्लिमेंटरी संवैधानिक प्रवृत्ति से, जो निश्चय ही उदारवादी प्रवृत्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, वास्तविक गाँधीवादी अहिंसक एवं असहयोगात्मक प्रवृत्ति ही मुथरी हो गई है।

फारवर्ड ब्लॉक का यह दोहरा कार्यक्रम लगातार, पहला कांग्रेस के वर्तमान कार्यक्रमों को सजीव एवं क्रान्तिकारी रूप देना और दूसरा देश को आने वाले संघर्ष के लिए देश व्यापी क्रान्तिकारी कार्यक्रमों से तैयार करना होगा। इस अग्रगामी कार्यक्रम को कांग्रेस आगामी दिसम्बर में स्वीकार करे इसके लिए अभी से आवश्यक प्रचार और संघर्ष को हम बढ़ाने में लग जाएं और दबाव बनाएं।

अगर अन्तिम तौर पर हमने यह पाया कि हमारी पार्लियामेंटरी मशीनरी या सूह आजादी के संघर्ष में आगे नहीं आता तो हम उनकी उपेक्षा करके, उन्हें छोड़कर जन संघर्ष या जन-सत्याग्रह विशिष्ट रूप में आरम्भ कर देंगे।

मैं प्रोग्राम के कुछ बिन्दु बताऊँगा। यह बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस स्वयंसेवक समुह का अखिल भारतीय स्तर पर विचारों से दक्ष बनाना होगा और साम्राज्यवाद विरोधी अन्य संगठन जैसे किसान सभा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूथ लीग तथा विद्यार्थी आन्दोलन से अति निकट का संबंध बनाना

होगा यह इसलिए आवश्यक है कि अगर हम देश की सारी उपलब्ध क्रान्तिकारी शक्ति को आजादी के संग्राम में शामिल करना चाहते हैं। फारवर्ड ब्लॉक के संगठन को बढ़ाते समय हम इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि कांग्रेस एवं दूसरे साम्राज्यवाद–विरोधी संगठन में बराबर निकटता बढ़े।

दूसरा बिन्दु प्रोग्राम का यह है कि देश में मौजूद बहुतेरी राज्यों यानी रियासतों में चल रहे जन–संघर्षों का कांग्रेस से अधिक नजदीकी संबंध स्थापित हो। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि देश में फैली 600 रियासतों में चल रहे जनता के संघर्षों से न केवल निकटता हो बल्कि कांग्रेस एक उपसमिति बनाए जो इन रियासतों के जनसंघर्षों का व्यापक प्रोग्राम बनाकर संघर्षों में सहायता करें। यह योजना पूरे देश में एक तरह से एक साथ चले।

इसके अलावा हमें अपना ध्यान अल्पसंख्यकों की खासकर हिन्दु–मुस्लिमों की समस्याओं पर देना होगा। इसके बावजूद कि अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को आवश्वासन देने के यद्यपि कांग्रेस द्वारा लगातार प्रस्ताव भी किए गए हैं, इसके बाद भी उन्हें हम सामान्य मंच पर लाने में समर्थ नहीं हो सके हैं। फारवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा और उसके क्रान्तिकारी प्रोग्रामों की अल्पसंख्यक समुदाय में अच्छी प्रतिक्रिया हुई है इससे यह आशा बलबती हुई है कि हम वास्तविक एकता स्थापित करने में समर्थ होंगे।

फारवर्ड ब्लॉक की कार्यशैली

(12 अगस्त 1939)

सन् 1920 में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में नाना प्रकार की आरम्भिक उथल–पूथल के बाद वामपंथियों ने इण्डियन नेशनल कांग्रेस पर अपना कब्जा कर लिया था। यह उस समय के सर्व श्री जिन्ना. वी. सी. पाल तथा वी. चक्रवर्ती नेताओं के कांग्रेस से बाहर होने का संकेत था। कांग्रेस में वामपंथी ही उसके प्रमुख बन गए वे वहाँ बहुत काफी बड़ी संख्या में हुए। 1922 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के स्थगित करने से पार्टी के अन्दर की बहुमत वाली पार्टी में मतभेद पैदा हो गए और अन्त में विधान सभाओं में भाग लेने के प्रश्न को लेकर दो भागों में स्वराज्य पार्टी वाले तथा परिवर्तन न चाहने वाले (दो भागों में) पार्टी बंट गई, कुछ समय बाद में स्वराजवादियों के विचार यानी विधान सभाएं भी लड़ने का माध्यम है इसको कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लेने से कांग्रेस फिर एक हो गई।

1928 में नेहरू कमिटी की रिपोर्ट के छपने के बाद जिसमें बहुमत डोमिनियन स्टेटस (संघशासन) स्वीकार करने की वकालत की गई थी .. उस समय भी कांग्रेस में 'इण्डिपेन्डेन्स लीग' के रूप में वामपंथ का उद्भव हुआ था। 1928 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में लीग के लोगों ने प्रयत्न किया कि कांग्रेस अपने लक्ष्य में परिवर्तन करे ताकि पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना कांग्रेस का लक्ष्य बन जाए, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिल पाई इस सुझाव का विरोध महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली मुख्य बनी कांग्रेस ने किया था। 'इण्डिपेडेन्स लीग' का झगड़ा बराबर एक साल तक चलता रहा। कांग्रेस के 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में महात्मा जी की सहमति से कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य पाना बन गया।

कांग्रेस के सभी ग्रुपों में समझौता हो गया और 1930 में चलाए गए सविनय अवज्ञा आन्दोलन में (लगान बन्दी समेत में) सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया।

193 में संघर्ष को स्थगित तथा 1934 में आल इण्डिया कांग्रेस कमिटी द्वारा पार्लियामेन्टरी कार्यक्रम अपनाने में वामपक्षियों में असंतोष फैला और उनमें टकराव उभरा उसी के परिणाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्भव हुआ और उसका तत्काल कार्यशैली निश्चय अभिनन्दनीय है जिसके ही कारण संवैधानिक की ओर तीव्रगति से बढ़ने पर रोक लगी। जल्दी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के भीतर रहकर काम कर रहे वामपंथियों का केन्द्र बन गई।

1934 से 1937 तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी संख्यात्मक तथा प्रभावात्मक दोनों ही प्रकार से प्रमुखता में रही – लेकिन फरवरी 1938 में हरिपुरा में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के समय यह अनुभव किया गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जितना अधिक प्रभावशाली होना चाहिए वह आगे भी उतनी ही अग्रगामी नहीं हो पायेगी। हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में मैंने कहा था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को साम्राजयवाद – विरोधी वामपंथी भूमिका कांग्रेस में निभानी चाहिये न कि केवल सोशलिस्ट – समाजवादी भूमिका। यही नहीं वह साम्राज्य विरोधी वामपंथी भूमिका निभायेगी तो वह आगे बढ़ेगी।

हरिपुरा कांग्रेस के बाद जिन सोशलिस्ट तथा कम्यूनिस्ट मित्रों से इस विषय पर चर्चा हुई सभी ने इससे सहमति जताई थी। आमतौर पर यह अनुभव किया गया कि सभी प्रगतिशील, क्रान्तिकारी तथा साम्राज्यवाद विरोधी साथी, जो सोशलिस्ट या कम्यूनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते उन सबको एक न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम के आधार पर इकट्ठा किया जाए। मैंने यह भी अनुभव किया था कि यही एक मात्र तरीका है जिससे न केवल दक्षिण पंथियों के हमले या दबाव को रोका जा सकता है बल्कि एक वास्तविक मार्क्सवादी पार्टी को विकसित होने का अवसर आ सकता है।

कांग्रेस की वर्तमान बहुमत पार्टी या गाँधी पार्टी का "गांधी सेवा संध एक लौह कवच" है। उसकी मार्च 1938 में उड़ीसा प्रान्त के 'देलाग' में बहुत महत्त्वपूर्ण अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में गाँधी सेवा संध ने वामपंथियों के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है। संध ने निर्णय लिया है कि वह अपने साथियों को मजदूरों के बीच भेजेगा ताकि मजदूरों के बीच वर्गीय चेतना फैलाकर जो मजदूरों के साथी ट्रेड यूनियन आंदोलन देश में कर रहे हैं, उनको हटाया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि वह अपने खास-खास लोगों को भेजेगा ताकि वे प्रान्तीय एवं दूसरी कांग्रेस कमिटियों पर अधिकार कर सके।

1934 में कांग्रेस ने जिस पार्लियामेन्टरी कार्यक्रम को स्वीकार किया था उसका अन्तिम परिणाम 1937 में मिनिस्ट्री (मंत्रिमण्डल) का कार्यभारत स्वीकार करने के रूप में हुआ। इससे दक्षिणपंथियों को अपने को और संगठित करने और संगठन को प्रभावित करने तथा 1938 में वामपंथियों के खिलाफ आक्रमणात्मक रुख अपने में समर्थ हो गए। वामपंथी अपने अस्तित्व बचाने में तभी समर्थ हो सकेंगे जब व होशियारी के साथ अपने को संगठित एवं अनुशासित बनायेंगे।

यदि कांग्रेस में शामिल सारे प्रगतिशील, क्रान्तिकारी तथा साम्राज्यवाद विरोध, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मंच पर इकट्ठा हो जाते तो बहुत से मसले आसानी से सुलझ सकते थे या सुलझाये जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसीलिए हरिपुरा कांग्रेस के बाद यह विचार बना कि तमाम वामपंथियों को एक समान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर "लेफ्ट ब्लॉक" (वामपंथी मंच) बनाया जाए अगर मौजूद वामपंथी पार्टियों, वामपंथी ब्लॉ (अब जिसका परिवर्तित नाम फारवर्ड ब्लॉक है) बनाने के दायित्व को पूरा कर पाती या कर लिया होता तो वामपंथी एकता (लेफ्ट कंसोलिडेशन) का काम बहुत आगे बढ़ चुका होता।

यद्यपि व्यक्तियों एवं ग्रुपों को ऐसा करने में सफलता नहीं मिली, लेकिन उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए इस समय जो वामपंथी उपलब्ध हैं उनको लेकर ही 'फारवर्ड ब्लॉक' का गठन किया गया। इसमें संदेह नहीं ब्लॉक (फारवर्ड ब्लॉक) बढ़ेगा और अपेक्षित रूप में विकास मार्ग में होने वाली तमाम दिक्कतों के बाद भी तीव्रगति से फैलेगा और जल्द ऐसा समय आयेगा जब आज जो शामिल होने में हिचकिचा रहे हैं अपने मन की दुविधा से बाहर आकर बढ़ी संख्या में शामिल होंगे। वामपंथी एकता कांग्रेस में बहुमत वाली शक्ति होगी और राष्ट्रीय संघर्ष के कार्यक्रम को आरम्भ करेगी। यही तीन बिन्दु का कार्यक्रम फारवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस में जो वामपंथी है उनके सामने है। जो हमारी आलोचना कर रहे या इस प्रयास में कमियाँ देख रहे हैं उन्हें कोई दूसरा सार्थक इससे अच्छा विकल्प प्रस्तुत करने दो। हम वैसे बने और सार्थक विकल्प में शामिल होने में जरा भी नहीं हिच किचायेंगे। जो हो, हमें डर है कि कोई दूसरा अच्छा सम्भव नहीं है।

संवैधानिक तथा सुधारवादी सोच से सोचने वाले दक्षिण पंथियों के कांग्रेस बचाई जा सकती है बशर्ते वामपंथी अपना क्रांतिकारी स्परूप बनाए रखें और कांग्रेस पर दबाव डाल कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संग्राम छेड़ने को तैया करें।

आज विभिन्न हिस्सों में समाजवाद बहुत ही सस्ता शब्द बन गया है। विभिन्न प्रान्तों में मिनिस्ट्री की गद्दी बहुतेरे मिनिस्टरी के समर्थक सोशलिस्ट पाए जाते हैं। हमें ऐसे समाजवादियों से जो दक्षिण पंथियों से चिपके हुए हैं, होशियार रहना होगा। केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमें सक्रियता में यकीन है। सच्चे समाजवादी को साम्राज्यवाद विरोधी भूमिका निभानी होगी और दैनिक कार्यवाहियों में वामपंथी कार्यशैली अपनानी होगी। वामपंथी नारा लगाना और मसालेदार भाषण देने से ही काम पूरा नहीं होता।

फारवर्ड ब्लॉक कांग्रेस सभी प्रगतिशील क्रान्तिचेता तथा साम्राज्यवाद विरोधी वे चाहे सोशलिस्ट हो या न हों एक करेगा। इसी प्रकार की एकता (कन्सालिडेशन) जनता को साम्राज्यवाद - विरोधी संघर्ष के लिए तैयार करेगी जिसके फलस्वरूप जन्म सिद्ध अधिकाररूपी स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। लेकिन राजनैतिक आजादी प्राप्त करने का अर्थ 'ब्लॉक' की समाप्ति नहीं होगी। इसका केवल एक मतलब होगा कि उसका निश्चय ही देश में समाजवाद की स्थापना करना उसका अगला दायित्व होगा।

आजादी के आंदोलन के महान क्रान्तिकारियों के इतिहास को समाप्त करने का केन्द्र के कांग्रेस सरकार का षड्यंत्रः डॉ मुर्तजा हुसैन

महाराष्ट्र के नागपुर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस घोषित करने के संदर्भ में दिनांक 15 जून को हिंदी मोर भवन में नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें डॉ. मुर्तजा हुसैन, कृषि मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार मुख्य अतिथि थे। डॉ. मुर्तजा हुसैन ने बताया कि चारों वामपंथी पार्टियों के केन्द्रीय नेताओं ने प्रधानमंत्री को लिखित पत्र में यह मांग की थी कि नेताजी जयंती को देश प्रेम दिवस के रूप में घोषित किया जाये । लेकिन सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इससे पूर्व राज्यसभा सांसद साथी बरूण मुखर्जी ने संसद में 17 दिसम्बर 2008 को स्पेशल मेंशन के जरिये भी मांग की थी, जिसके जवाब स्वरूप 16 मार्च 2010 को संसदीय कार्य एवं योजना मंत्री वी. नारायणासामी का लिखित जवाब आया। जिसमें आजादी के आंदोलन में अनेकों ने बलिदान किया है। अतः किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ऐसी

घोषणा करना संभव नहीं है। हम आजादी के आंदोलन में भाग लेनेवाले सभी को सलाम जय हिन्द करते हैं। मगर आजाद हिंद सरकार के भारत के पहले राष्ट्रपति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की उनसे तुलना करना यह कांग्रेस के नजरिये को दर्शाता है। ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना की घोषणा नेताजी बोस ने कांग्रेस से इस्तिफा देकर रामभाउ रूकर को देकर इसी नागपूर शहर से 1939 को की थी। अत: नागपूर के लोगों की यह जिम्मेदारी है की, देश प्रेम दिवस को लेकर वह भारत को जगाये।

नेताजी सुभाष फाउण्डेशन के राजय अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भलचंद्र जोशी इनकी अध्यक्षता में संपन्न नागरिक सम्मेलन में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. श्रीनिवास खोदेवाले, माकपा युवा नेता साथी अरूण लाटकर, इन्होंने भी अपने विचार रखें। डॉ. खोदेवाले ने कहां की नेताजी का आजादी के आंदेालन में बड़ा महिलाओं की फौज बटालियन तैयार की थी। सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लोगों को लेकर आजाद हिन्द सरकार का गठन किया था। पण्डित नेहरू तथा महात्मा गाँधी इन्हें समाजवाद मान्य नहीं होने के कारण नेताजी की उनसे मत भिन्नता थी। साम्राज्यवाद के खिलाफ के संघर्ष को नेताजी ने ही दुनिया के अन्य राष्ट्रों में पहुँचाया। अत: नेताजी के जन्मदिन को 'देशप्रेम दिवस' के रूप में मान्यता केन्द्र सरकार दें कैसी मांग उन्होंने की। नौजवानों में जागृती हेतु स्कुल-कॉलेजों में कैसे सम्मेलन आयोजित करने पर उन्होंने रोक दिया। साथी अरूण वांकर ने कहा कि बहुमत से चुनकर आने के बावजूद कांग्रेस के अधीन होने पर कांग्रेस ने उन्हें स्वीकार नहीं किया वह कांग्रेस 'देश प्रेम दिवस' घोषित करेगी यह संभव नहीं।

अध्क्षीय भाषण करते हुये डॉ. श्रीपाद जोशी ने कहां की भूमण्डलीकरण के युग में राजसत्ताओं ने समाजवाद को नकारा है। जब राष्ट्र का ही कंपनीकरण किया जा रहा है तब क्या राष्ट्रवाद जिंदा रहेगा ?सरकार आई.पी.एल. के नाम से क्रिकेट सट्टा चला रही है, शिक्षा को व्यापार का रूप दे रही है। अगर नेताजी सुभाष को यह सरकार स्वीकृत कर ले तो यह राज नहीं कर पायेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन किसी एक पार्टी की भक्तेदारी नहीं हो सकती। 90 साल चले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने अनेकों गुलाम राष्ट्रों को आजादी के संघर्ष की प्रेरणा दी। भगत सिंह और नेताजी सुभाष यह वह शख्स है, जो किसी भी पीढ़ी के दिमाग से नहीं निकाले जा सकते। गांधी - अहिंसा, नेहरू - बाल दिवस, राजीव गाँधी - एन्टी टेररिस्ट डे के नाम पर इनके दिन की घोषणा होती है। मगर जिस महात्मा गाँधी तक को नेताजी सुभाष को 'देश भक्तों का देश भक्त' कहना पड़ा, उसी कांग्रेस के मंत्री नारायणासामी नेताजी सुभाष की तुलना किसी एक व्यक्ति से करते हैं। जो बेशरमपना की हद है। 'देश प्रेम' को ठुकराने का अर्थ है, देश की जनता को नकारना। जो भी राजकर्ता हो वह जन इतिहास लिखने की बात करता है तब वह अपने राजसत्ता के अनुकूल ही इतिहास लिखता है। अत: हम घोषित करते हैं कि 23 जनवरी - देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जायेगा। जो मानेंगे वह जनता के पक्ष में और जा नहीं मानेंगे वह जनता के विरोध में। लॉ एटली ने लिखा है कि 'चले जाओ' आंदोलन के कारण नहीं बल्कि आजाद हिन्द सेना जो हमारे खिलाफ हिन्दुस्तान के ओर आ रही थी। उसकी प्रेरणा से कही हमारी सेना ही हमारे खिलाफ विद्रोह खड़ा न कर दें। इस कारण हमें हिन्दुस्तान के साथ आजाद का समझौता करना पड़ा। सुभाष ने 'सारी सत्ता जनता के हाथ में' इस समाजवाद और लोकतंत्र के नारे को अमल में लाने हेतु 'देश प्रेम' की भावना निर्माण करने हेतु जूट जाने का उन्होंने आह्वान किया।

फारवर्ड ब्लॉक के प्रदेश महासचिव साथी अरूण वांकर ने प्रस्ताव रखते हुये कहा कि 'आजाद हिन्द सरकार' की स्थापना दिवस 23 अक्तूबर इसके उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के सभी स्कूल, कॉलेजों के छात्रों हेतु 'नेताजी जयंती 23 जनवरी देश प्रेम दिवस के रूप में घोषित करो कि विषय पर निबंध स्पर्धा का आयोजन कर फिर आजादी के आंदोलन को जिंदा किया जायेगा। जिसे सभी ने मान्य किया।

इसके अलावा सम्मेलन को साथी बलवंत राय मेहता ने भी संबोधित थे। अन्य प्रमुख लोगों में मा. उमेश चौबे, सवामी संजय कटकमवार, साथी शेरलिंग नाहर, धीमनी, विद्या कोनके आदि गण मान्य नागरिकों के साथ-महीला प्रमुख हॉल में उपस्थित थे। सम्मेलन की सफलता हेतु साथी दीपक वाघमारे, साथी प्रविण गभणे आदि ने विशेष प्रयास किया।

कार्यक्रम का संचालन साथी अरूण वनकर तथा आभार प्रकट साथी धर्मराज राउत ने किया।

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अन्तर

श्याम सुन्दर बिश्नोई, मध्य प्रदेश

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के मध्य प्रदेश इकाई अध्यक्ष साथी श्याम सुन्दर बिश्नोई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करतु हुए प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि जो सरकार बिजली, पानी एवं सड़क के सुधार के आश्वासन के बल पर सत्ता में आई थी एवं वादा किया था कि हम सौ दिनों में बिजली की व्यवस्था सुधार कर देंगे, वहीं सरकार बिजली में सुधार न करके हर तीन माह या छ: माह के अंतराल पर बिजली की दें बढ़ाने के कार्य में लगी है।

निजी कम्पनियों की तर्ज पर, जिस प्रकार कोई निजी कम्पनी अपने उत्पाद के मूल्य वृद्धि करती है तो सर्वप्रथम वह मूल्यवृद्धि करके अपने उत्पाद के साथ कुछ फ्री गिफ्ट की घोषणा कर देती है जो कुछ दिनों के लिये होती है और मूल्य वृद्धि दिर्घकालीन हो जाती है, उसी तरह से सरकार ने पेशेवर रवैया अपनाते हुये इस महँगाई में सरकार ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तथा किसानों को गेहूँ के समर्थन मूल्य पर 1008 रुपये का बोनस तो दिया,

लेकिन सरकार उसे किसी भी तरह वापस वसूल करना चाहती है, चाहे वह बिजली की दर बढ़ाकर हो या किसी अन्य तरीके से। यानि एक हाथ से दिया एवं दूसरे हाथ से लिया, जो जनता के साथ सीधा–सीधा छल है।

चमकता भारत या भूखा भारत?

डॉ. वन्दना शिवा

बंगाल के भयावह अकाल, जिसमें बीस लाख लोग मारे गये, के तुरन्त बाद भारत आजाद हो सकता था। इस तरह स्वतंत्र और मुक्त भारत में खाद्य आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की घोषणा हो चुकी होती।

महात्मा गाँधी के द्वारा प्रकाशित हरिजन समाचार पत्र, जो 1942 से 1946 तक प्रतिबंधित था, इस पत्र में 1946–1947 के दौर में गाँधी के कई लेख इस संदर्भ में प्रकाशित है, जिनमें बताया गया है कि खाद्य संकट को कैसे राजनैतिक रूप से निपटाया जा सकता है। साथ ही मीरा बहन, कुमाराप्पा और प्यारे लाल ने आंतरिक संसाधनों का प्रयोग करके और अधिक अन्न उगाने की तरीके सुझाये है। 10 जून 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में संबोधित करते हुये गाँधी ने खाद्य समस्या पर प्रकाश डाला और कहा:

"पहला पाठ जो हमे अवश्य सीखना चाहिये वह 'अपनी मदद स्वयं करना' और 'आत्मनिर्भर बनना' चाहिये। यदि हम इस पाठ को चरितार्थ करते हैं तो हम उसी क्षण विदेशों पर निर्भर रहने की भयावह प्रवृत्ति और उससे ऊपजा दिवालियापन इन दोनों से मुक्त हो जायेंगे। यह मैं किसी कुण्ठा या आवेश में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह यथार्थ है। हमारा देश छोटा देश नहीं है, और खाद्य आपूर्ति के लिये विदेशों की मदद पर आश्रित है। हम एक उपमहाद्वीप है, 40 करोड़ की आबादी वाला एक विशाल देश है। हमारा देश शक्तिशाली नदियों का देश है और यहाँ की कृषि भूमि कई किस्म की उर्वर गुणवत्ता युक्त है तथा हम कभी न खत्म होने वाले विशाल पशुधन के मालिक हैं। यदि हमारे पशु हमारी आवश्यकता से कम दूध प्रदान करते हैं तो इसमें हमारा दोष है। हमारा पशुधन किसी भी दिन हमारे दूध की आवश्यक आपूर्ति को पूरा करने में सक्षम हो सकती है। हमारा देश जो विगत कुछ शताब्दियों से उपेक्षित रहा है, अन्यथा आज हमारा देश पूर्ण रूप से खाद्य निर्भरता प्राप्त कर चुका होता और दुनिया के दूसरे देशों को जिनमें अधिकांश वे दुर्भाग्यशाली देश है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध का अभिशाप झेलना पड़ रहा है, को खाद्यान्न प्रदान कर रहे होते। आज हमारा भारत इससे अछूता नहीं है।"

भारत के पहले कृषि मंत्री श्री के. एम. मुंशी ने कृषि क्षेत्र के इस संकट को पहचाना और इसे प्रकृति के स्वभाविक चक्र में दखल डालने से जोड़ा। उन्होंने निचले स्तर पर विकेन्द्रीयकरण और सहभागिता के सिद्धांत पर कृषि क्षेत्र की पारिस्थितिक उत्पादकता को पुनर्गठित और पुन: सृजनशील बनाने के उद्देश्य से विस्तृत अध्ययन कर एक विस्तृत कार्य किया था।

भारत की कृषिभूमि, फसलों (पैदावार) और पर्यावरण की विविधता को ध्यान में रखकर कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि के पुन: सृजनशील करने के कार्यक्रम पर कार्य किया और 27 सितम्बर 1951 को इस संदर्भ में एक सेमिनार का आयोजन किया। नीचले स्तर पर कार्य करने की योजना बनाई गई, जिसमें प्रत्येक गाँव और कभी प्रत्येक व्यक्तिगत खेत पर विचार की आवश्यक योजना बनाई गई तथा इसे कार्यक्रम को 'भूमि संक्रमण' नाम दिया गया। उक्त सेमिनार में राज्यों के कृषि विस्तार निदेशकों को सम्बोधित करते हुए श्री के.एम. मुंशी ने कहा –

'अपने निर्देशन में हाइड्रोलाजिकल और पोषणता दोनों सन्दर्भों में गावों में जीवन चक्र का अध्ययन कीजिए। यह चक्र कहाँ दुष्प्रभावित हुआ है इसके कारणों का पता लगायें और इसके पुनर्जीवन और प्रभावी होने के लिए आवश्यक आकलन सुझाएँ। गांवों की चार तरह से अध्ययन करें – (1) वर्तमान परिस्थितियाँ, (2) हाइड्रोलाजिकल चक्र के पूरा होने के आवश्यक कदम, (3) पोषणता चक्र को पूरा होने के आवश्यक कदम और इस चक्र के पूरा होने की दशा में गाँव की पूरी तस्वीर क्या होगी और (4) स्वयं पर विश्वास करें और इस कार्यक्रम में आस्था रखें।'

प्रकृति के चक्र को दुरुस्त करने और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ सहभागिता में कार्य करने को स्वाभाविक कृषि नीति के केन्द्रीय विचार के रूप में देखा गया।

जल और पोषणता के चक्र के साथ भूमि सुधार के परिस्थितीय सुधार, कृषि और उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य निर्धारण खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के आवश्यक कारक हैं।

खाद्य प्रक्रिया एक बार फिर बिगड़ गयी। प्रति व्यक्ति औसत खपत 117/कैलारी/प्रतिदिन/प्रव्यिक्ति से घटकर 150/कैलारी/प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति हो गयी। और इस बिगड़ती प्रक्रिया को विश्व बैंक ने विश्व व्यापार संगठन के उदारीकरण व्यापार के मद्देनजर संरचनात्मक नीतियों के माध्यम से जानबूझकर किया है। कारपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए सरकार ने बीज, खाद्य और जमीन को बाजार की सामग्री बना दी जिसके कारण इसका बिगड़ना लगातार जारी है, जबकि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बच्चे भूखे सो रहे हैं। भारत में 1997 के बाद से 2,00,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण कर्ज लेना है, और यह कर्जा के बोझ कारपोरेटरों द्वारा संचालित

कृषि व्यवस्था है, जो अधिक मुनाफा कमाने के लिये निर्दोष किसानों को अनवीनीकरणीय बीज और रसायनों के प्रयोग के लिए धकेल दिया।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक चौथा भारतीय भूखा है। भूख की राजधानी के रूप में भारत ने अफ्रीका की उप-सहारा देशों को भी पीछे छोड़ दिया। प्रत्येक वर्ष 1 लाख बच्चे भूख और पोषण की कमी के कारण मर जाते हैं। 61 लाख बच्चे अचेत है, 25 लाख खराब हो जाते हैं। दुनिया के कमजोर बच्चों में 42 प्रतिशत सिर्फ भारत में है। अगर एक समुदाय भूखा रहता है, पूरा परिवार भूखा रहता है, अगर परिवार भूखा रहता है, तो बच्चे भी भूखे रहते हैं।

अगर पूरी खाद्य प्रक्रिया बिगड़ जाती है तब खाद्य प्रक्रिया तय किया जाना चाहिये। टूटी हुई कड़ी के टुकड़ों को बजाते रहना ठीक नहीं होता। खाद्य प्रक्रिया का आरम्भ प्राकृतिक संशाधनों - मिट्टी, पानी और बीज से होनी चाहिये। दूसरी कड़ी होनी चाहिये छोटे, सिमांत किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों की, जिमने अधिकतर महिलाएं होती है, द्वारा कड़ी मेहनत। और अन्त की कड़ी होनी चाहिये भोजन।

जिसमें पहली कड़ी के टूटने का कारण है पर्यावरणीय दुर्दशा और कारपोरेटरों द्वारा बीज, भूमि और पानी पर अधिकार जमा लेना। खाद्य की असुरक्षा में मृदा क्षरण, जैव विविधता, पानी की कमी, आदि के कारण खाद्य उत्पादन के गीरते स्तर के कारण है। जब किसान के पास खेत, बीज और पानी की कमी हो जाती है तो खाद्य की भी कमी हो जाती हैं। भूखमरी बढ़ने का एक सीधा परिणा है।

दूसरी कड़ी के टूटने का कारण है, किसानों की क्षमता, खाद्य उत्पादन करने वाले खाद्य उत्पादनकर्ता। उत्पादन की वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और खेतों के गीरते दामों से कर्ज बढ़ गया और कर्जे के कारण खाद्य असुरक्षा पैदा हो गयी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जानबुझकर खराब करके सोची समझी चाल के तहत खाद्य उत्पादनों को बर्बाद को बरबाद करना, गोदामों का इस्तेमाल मदीरा के प्रयोग के लिए करना खाद्य सामग्रियों के लिये नहीं, भारत के किसानों को उनकी उत्पाद का उचित मूल्य न देकर सरकार संकेत दे रही है कि वह छोटे किसानों के बिना खाद्य सुरक्षा बनाना चाहती है। हालांकि किसान भारत की खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता की रीढ़ की हड्डी है, किसानों की कमर तोड़ने का अर्थ है राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को तोड़ना। इस प्रकार कृषि संकट बनाकर खाद्य सुरक्षा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता।

खाद्य श्रृख्ला में तीसरी कड़ी है जनता की पात्रता और भोजन का अधिकार। बढ़ते महँगाई के साथ-साथ, दालों और अनाजों के उत्पादन में गिरावट से गरीबों में पर्याप्त खाद्य और पोषण की कमी हुई है। भूख और कुपोषण अपरिहार्य परिणाम हैं।

एक ओर जहाँ लाखों नागरिक भूखे रहते हैं, वहीं सरकार आंकड़ों के साथ छेड़-छाड़ में लगी रहती है। सरकार का कार्य खाद्य सुरक्षा से लड़ना है, लेकिन यह परिणामों के छोटे से घटनाक्रम में खोई रहती है। गरीबी एक नतीजा है, निष्कर्ष है, एक घटना नहीं है। तेंडुलकर कमिटी रिपोर्ट के फिगर को देखें तो 37 प्रतिश, सक्सेना रिपोर्ट में 50 प्रतिशत और असंगठित क्षेत्र की रिपोर्ट में 77 प्रतिशत में दर्शाया गया है कि भूख और गरीबी की मूल जड़ को अनदेखा किया जा रहा है। भोजन और पोषण के संदर्भ में तैयार किया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) मात्र दिखावा है। यह बहुत ही अपर्याप्त है क्योंकि इसमें खाद्य कड़ी की दो श्रृंख्लाओं को अनदेखा किया गया है और विद्मान योजना में गरीबों और कमजोर कड़ियों को छोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए - नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार एक परिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित प्रतिमाह 35 किलो अनाज की जगह 25 किला अनाज का प्रावधान है। इण्डिया काउसिंल ऑफ मेडिकल रिसर्च (चिकिस्तसा अनुसंधान परिषद्) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलारी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी में का मानदंड रखा है। तेंडुलकर कमिटी जो अब योजना आयोग की अधिकारिक आधार है, ने शहरी क्षेत्रों के लिये 1176 कैलोरी तथा 1999 कैलारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए का प्रावधान दिया है। इस प्रकार के करतबी आंकड़ों के माध्यम से भूखें अच्छे खाते पीते बन जाते है और गरीबों की गरीबी खत्म हो जाती है।

खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौम करना आवश्यक है, इस खाद्य कड़ी से सभी को उचित दाम पर गरीब किसानों या जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता है भोजन उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन सरकार इसके उलट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खत्म करते जा रही है और खेती को ध्रुवीय कृषि व्यवसाय बना रही है और हमारी खाद्य सुरक्षा की मांग को इन कंपनियों के योजना में समाहित कर रही हैं, जैसे सोडेक्सो हमारी टैक्स के पैसे वसूल करेगा और भोजन के लिए गरीबों को कूपन वितरित करेगा, इस भोजन के कूपन की योजना से कारगिल, युनीलिवर, नेसले आदि जैसी कम्पनियों को मुनाफा पहुँचाने के लिये करेगा।

सरकार के इस तरीके से हमारी खाद्य सुरक्षा की कड़ी को और नुकसान पहुँचायेगी और हमारी खाद्य असुरक्षा अधिक गहरायेगा।

कृषि व्यवसाय के कारण छोटे किसान विस्थापित हो रहे हैं तथा वास्तविक पूँजी बर्बाद हो रही है जिससे खाद्य श्रृंख्ला की पहली कड़ी और अधिक कमजोर होती जा रही है। भारत की ग्रामीण क्षेत्र की दो-तिहाई कृषि समस्या गहरा रही है। और खाद्य स्टाम्प तथा खाद्य वाउचर के जरिये उत्पादन एवं उपभोग के मध्य किसानों तथा भोजन करने वालों के संबंध के टूटने से खाद्य श्रृंख्ला पूरी तरह टूट जायेगी।

एक बड़े देश के लिये, गरीब और भूखे भारत के लिए खाद्य संप्रभुता और उत्पादन में आत्मनिर्भरता विलासिता नहीं है, बल्कि यह तो खाद्य सुरक्षा होती है।

प्रस्तुत समाधान में खाद्य सब्सिडी घटा दिया गया। यह एक बड़े ही बहस की मुद्दा है कि विश्व बैंक के दबाव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को

लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदल दिया गया। जबकि, हमारे देश के भूखे लोगों के लिये खाद्य सब्सिडी विधेयक 2500 करोड़ रुपये से बढ़कर 50000 करोड़ रुपये कर दिया गया। आगे इस लक्ष्य को 'संकुचित' करते हुये खाद्य सब्सिडी और बढ़ायेंगे, क्योंकि उत्पादन खर्च एवं रियायती खाद्य और अधिक महँगा होगा ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार बाजार भाव की कीमतें और रियायती सामानों की कीमतें में अन्तर बढ़ रहा है। और इस बढ़ते अंतर के कारण भ्रष्टाचार बढ़ेगा। एनरॉन, गोल्डमेन सैच एवं आईपीएल के बाद निजी क्षेत्र को किसी भी स्थिति में साफ सूथरा कहना गलत होगा। भ्रष्टाचार पर लगाने के बारे में हमें उस सरकार से जो खाद्य वस्तुओं को गरीब आवश्यक लोगों से छीनकर मुनाफाखोरों के हाथ मं बेच रही है, उम्मीद छोड़ देनी चाहिये तथा भूखमरी की समस्या के निवारण का ख्याल त्याग देना चाहिये।

क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य कानून में बदलना है, जो वास्तव में हमारी राष्ट्रीय खाद्य असुरक्षा अधिनियम हैं।

नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में भूख हड़ताल और धरना

कन्नौज (उत्तर प्रदेश) : अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की जिला समिति के तत्वावधान एवं नगर पालिका परिषद के प्रांगण में भ्रष्टाचार के विरोध में आज कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। इसके साथ ही प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को सम्बोधित एक ज्ञापन भी प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।

मजे की बात यह है कि घंटों इंतजार करने के बाद जब कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुँचा तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। कस्ता इंचार्ज प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा व्यवस्था ममें दिन भर जुटे रहे। फारवर्ड ब्लॉक के जिलाध्यक्ष महेन्द्र सिंह टिकैट, महामंत्री के.के. राठौर एवं प्रदेश महासचिव दबीरूल हसन के नेतृत्व में नगर पालिका परिषण प्रांगण में दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन करते हुये भूख हड़ताल की।

मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद कार्यालय के बाहर गेट से सुरेश जी के मकान तक इंटरलॉक रोड़ का निर्माण कराया गया जिसमें इस्टीमेट के अनुसार मानकों को पूरा नहीं किया गया। इसके साथ ही जे.ई. द्वारा फर्जी भुगतान करा दिया गया। रामलीला मैदान में जो मिट्टी भराई और दीवार निर्माण कार्य कराया गया वह भी गलत है जिसमें लाखों रुपये का जे.ई. द्वारा बिल बनाकर फर्जी भूगतान कराया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि मैदान में मौजूद तालाब में मिट्टी डालकर भराने का कार्य रामलीला कमिटी द्वारा काराया गया है। कुछ काम नगर पालिका द्वारा भी कराया गया है लेकिन मैदान को ऊँचा उठाने के लिए लाखों रुपये का फर्जी भुगतान कराया जा रहा है जो गलत है।

नगर पालिका द्वारा नगर में लाखों रुपये कीमती हाई मार्क्स लाईटें लगायी गयी जो आज तक नहीं जलीं। घटिया किस्म की लाईटों की जाँच कराकर बंद पड़ी लाइटों को जलवाने की व्यवस्था की जाये। नगर में पेयजल संकट से जनता जूझ रही है। इस समस्या को हल करने के लिए नगर में ट्यूबबेल एवं टंकी बढ़ाने की व्यवस्था की जाये। लाखों रुपये कीमत की खरीदी गयी बंद पड़ी फागिंग मशील को तत्काल चलवाया जाये। नाले, नालियां एवं गंदे स्थानों पर कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग कराया जाये। फतेहगढ़ रोड साईड में डाक बंगला से बाईपास तक पार्क बनवाकर एवं डिवाइडर बनाकर सुंदरीकरण कराया जाये। बाईपास के पास सुलभ शौचालय निर्माण कराया जाये। धरने में सिपाही लाल, बादाम सिंह, राकेश, राम किशोर, कैलाश, सुभाष, दयाराम, राम विलास, दुर्योधन, प्रेम कुमार गिहार, जगत सिंह, सोमवती, बलकोरा, सरस्वती, शारदा देवी, अनिल कुमार वर्मा, मो.रफीक, अमित कमार राठौर, शहाबुद्दीन मंसूरी, नीरज कुमार, अनवार खां, मुनीर कुरैशी आदि उपस्थित रहे।

झारखण्ड में नया जनादेश ही एकमात्र विकल्प

जनार्दन पाण्डेय

राँची : झारखण्ड में 153 दिनों की भाजपा एवं झामूमो की अवसरवादी गठबंधन की सरकार अंततः गिर गई एवं सूबे में दुबारा राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। केन्द्र की यूपीए सरकार के खिलाफ कटौती प्रस्ताव पर 27 अप्रैल 2010 को शिबू सोरेन द्वारा मतदान किये जाने के सवाल पर एक माह चार दिनों तक भाजपा, कांग्रेस एवं झामूमो का लुक्का छिपी का खेल जारी था एवं सूबे की सरकार कोमा में आ गयी थी। इस अवधि में झामुमो का एवं भाजपा की गद्दी पिट गयी। इनका अवसरवादी चेहरा जनता के सामने आ गया। कांग्रेस ने बड़े ही चालाकी से झामुमो पर डोरा डालकर अंततः प्रदेश में

राष्ट्रपति शासन का रास्ता साफ कर अप्रत्यक्ष रूप से सूबे की शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया।

झारखण्ड में नया जनादेश ही एक मात्र विकल्प रह गया है। राष्ट्रपति शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था से कतई बेहतर नहीं हो सकता है।

राज्यपाल के समक्ष काफी चुनौतियां है। राज्य में पंचायत चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 12 जनवरी 2010 के फैसले में झारखण्ड में अविलंब पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। सूबे में 32 वर्षो से पंचायत चुनाव लंबित है। इसके अलावा राज्य उग्रवाद एवं भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह फँसा हुआ है।

आन्ध्र प्रदेश में फारवर्ड ब्लॉक की सक्रियता

मुरलीधर देशपाण्डे

हैदराबादः देश प्रेम दिवस सम्मेलन की पूर्व संध्या पर अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की आन्ध्र प्रदेश राज्य कमिटी की बैठक दिनांक 7 जून 2010 को किया गया, तथा यह तय किया गया कि पार्टी स्थापना दिवस 22 जून 2010 से 28 जून तक आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। जिसके तहत 22 जून को हस्ताक्षर अभियान, 23 जून को सामूहिक सभाओं का आयोजन, 24 व 25 जून को स्कूलों व कॉलेजों में जागरूकता अभियान, 26 जून को जिला कलैक्टर को ज्ञापन सौंपा जायेगा, 27 जून को नुक्कड़ सभाओं का आयोजन और 28 जून को राजभवन मार्च निकाला जायेगा।

इसके अलावा 9 जून को हैदराबाद स्थित सीपीएम कार्यालय में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 8 वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया, तथा बढ़ती महँगाई के कारण गरीबों और मध्यम वर्ग परिवारों की समस्याओं, विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को दी जाने वाली भुगतानों की अदायगी न होने पर चर्चा की गयी तथा आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गयी। इन कार्यक्रमों के अनुरूप विशाखापत्तनम जिला के रामबेली गाँव, में 12 जून को धरना प्रदर्शन किया गया।

14 जून 2010 को करीमनगर जिला में फारवर्ड ब्लॉक की जिला स्तरीय सभा का आयोजन किया जहाँ विभिन्न सदस्यता अभियान सहित कई कार्यक्रमों की घोषणा की गयी।

विदेशी विश्वविद्यालयों का मुनाफे के लिये प्रवेश

सीमित शिक्षा

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का आरम्भ होना एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हैं। इन विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों की तादाद शायद अधिक से अधिक हो सकती है जो एक विदेशी विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे। लेकिन अन्त में, इससे इन्हें एक अच्छी नौकरी मिल मिलेगी या नहीं इसमें अनिश्चितता है, इससे अच्छा तो इन छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता तो ये प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होता।

इसके विपरीत, यदि भारतीय चाहे तो भी विदेशी सरकारें भारतीय विश्वविद्यालयों को अपनी धरती पर खोलने की अनुमति नहीं देंगे, कई अपरिहार्य कारणों से इन विश्वविद्यालयों में छात्र दाखिला भी नहीं लेते, अतः इससे भारतीय विश्वविद्यालयों को इसमें आर्थिक लाभ भी नहीं मिलता।

अतः, भारत भूमि पर विदेशी विश्वविद्यालयों के खुलने से शैक्षणिक और आर्थिक रूप से दोनों कदम एक समान नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के शोषण से बचने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारतीय जनता के फायदे के बारे में सोचना चाहिये जो कि आज ध्रूवीकरण और राष्ट्रीय संदर्भ में बहुत ही आवश्यक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बढ़ीया तरीका होता कि इन विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का स्तर भारतीय पद्धति पर आधारित होता और इसकी देख-रेख भारत सरकार या सरकार से संबंधित संगठन की निगरानी में होता।

उच्च शिक्षा के दो वस्तु विशेष हैः (1) बुनियादी सिद्धांतों की जटलता एवं तथ्यों का शोधों द्वारा ज्ञान अर्जित करना तथा मानव जीवन के बेहतर जीवन के लिये इस ज्ञान को नए प्रोद्योगिकी विकास में प्रयोग करें। (2) स्नातक की शिक्षा और नवीनतम घटनाओं की जानकारी के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी का अध्ययन करना।

हालांकि, यह भी कहा जाता है कि अच्छी स्नातक एवं पेशेवर शिक्षा के लिये अनुसंधानों के जरिये नए ज्ञान का सृजन आवश्यक है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा में अनुसंधान कार्यक्रमों के न होने से स्नातक और पेशेवर पाठ्यक्रमों में अच्छी शिक्षा की बात करना उचित नहीं होगा।

आधुनिक अवधारणा के अनुसार 'विद्या एक पूँजी है'। सभी देश गौरव और सम्मान के लिये अनुसंधान ज्ञान पर विशेष ध्यान देती है। माता-पिता वैश्विक औद्योगिकरण में आर्थिक लाभ हेतु पंजीकृत है। मुख्यतः, विदेशी सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम में, और भारतीय शोधकर्ताओं का विदेशी प्रयोशालाओं में कार्यरत होना। हालांकि, इन अनुसंधान कार्यक्रमों से प्राप्त शोध मेजबान देश की संपत्ति और पेटेंट बन जाती है। यद्यपि इन भारतीय शोधकर्ताओं को भारत वापस बुलाकर इनका अनुभव हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में असंतुलन को

उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों में सुधार लाना चाहिये।

ऐसे बहुत ही कम अवसर आते हैं जब, कला और संस्कृति की शिक्षा के लिये भारत में विदेशी से शोधकर्ता आते हो, इस प्रकार के शोधों के लिये दोनों देशों के मध्य तालमेल होना चाहिये।

विदेशी विश्वविद्यालय साधारण ज्ञान के प्रसारण के इच्छुक है, जैसे स्नातक और पेशेवर शिक्षा में शिक्षण कार्यक्रम बाजार की शक्तियों पर आधारित है। हालांकि, हमें इन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिये।

भारत की युवा आबादी का विकास दर विकसित देशों से ज्यादा है। वर्तमान परिस्थिति में, ऐसा मानना चाहिये कि भारत युवा छात्रों के आवश्यकतानुसार सुविधा मुहैया कराने का इच्छुक नहीं है।

देश की आर्थिक प्रगति के कारण, मध्यम वर्ग की आमदनी में इजाफा हुआ है। परिवार छोटे हुये है और माता-पिता अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिये कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है ताकि वे दुनिया में कहीं भी अच्छी नौकरी पा सके।

भारत मानसिकता में यह धारणा बनी हुई है कि भारतीय डिग्री की तुलना में विदेशी डिग्री काफी बेहतर है, यद्यपि यह अमेरिका और यूरोप के विशेषकर विज्ञान विषय के विश्वविद्यालयों के को छोड़ दें तो यह पुरा सत्य नहीं है।

विकसित देशों में इन अवधारणाओं से उच्च शिक्षा के भागों में अच्छी आर्थिक प्राप्ति के लिये ज्ञान में सहयोग (स्नातक और पेशेवर पाठ्यक्रमों में शिक्षा) फैला हुआ है।

मेरे विचार से, यदि हम क्षेत्रिय और राष्ट्रीय विकास के प्रति जागरूक है तो भारत को विदेशी विश्वविद्यालयों के अनुभवों और कार्यों को ग्रहण करना चाहिये, लेकिन इसका भौतिका ज्ञान, संस्कृति, ऐतिहासिक परिदृश्य और अन्य स्थानीय एवं राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना होगा। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि भौतिक और सांस्कृतिक में भिन्नता होने के कारण विदेशी शिक्षा की आवश्यकता हमें सीमित आवश्यकता में हो या विदेशी शिक्षा का आधार उनकी भौतिक और सांस्कृतिक स्थिति के कारण हमारे देश में उनकी आवश्यकता कम हो।

अंत में, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही सभी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में विदेशी सहयोग के पहले भारत की क्षेत्रिय व राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही उसमें सहभागिता करके उसके आधुनिकीकरण और बदलाव करना चाहिये।

(लेखक यूजीसी के अवकाश प्राप्त व्यक्ति है और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में भौतिकी के प्रोफेसर है)

साभार - अमिटी (हिन्दी रूपान्तरण प्रकाशन विभाग अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक)

कोचि में अग्रगामी महिला समिति की केरल राज्य सम्मेलन आयोजित

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति (अखिलेण्डिया पुरोगमना महिला समिति) की राज्य सम्मेलन क आयोजन कोचि में 22 और 23 मई 2010 को आयोजित की गयी। कोचि में पलारिवट्टम के व्यापारी भवन में प्रतिनिधि सत्र का आयोजन किया गया। केरल के विभिन्न 9 जिलों से 265 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन पुरी तरह सफल रहा। सम्मेलन स्थल और आस-पास का क्षेत्र झण्डों, फ्लैक्स बोर्ड आदि से सजा हुआ था।

प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति की केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष साथी अपर्णा सेनगुप्ता ने किया। प्रतिनिधि सत्र को संबोधित करते हुये साथी अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि केरल की महिलायें अपने अधिकार और समानता के लिये संघर्ष में अग्रणी रही है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ही थे जिन्होंने सर्व प्रथम महिला शक्ति को पहचाना था और आजाद फौज में एक अलग 'रानी झांसी रेजिमेन्ट' बनाया था। महिला आरक्षण बोलते हुये, उन्होंने कहा कि अग्रगामी महिला समिति अन्य महिला संगठनों, जो आरक्षण की मांग करती है, के साथ मिलकर लगातार संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि करेल की अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति नेताजी की धरोहर को ऊँचा रखेंगी और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लक्ष्य को अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति आगे बढ़ायेगा।

सम्मेलन में पश्चिम बंगाल की विधायक साथी डॉली रॉय प्रमुख अतिथि थी। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुये साथी डॉली रॉय ने कहा कि अग्रगामी महिला समिति की केरल इकाई को नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिये आगे आना होगा। उन्होंने मांग किया की हमारी जनसंख्या की 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं की है, जिन्हें उनका मौलिक अधिकार मिलना चाहिये और प्रशासनिक कार्यो व नीति निर्धारण में बराबर का हक मिलना चाहिये इसके बिना लोकतंत्र अधूरा है।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी एन. वेलप्पन नायर सम्मेलन के मुख्य वक्ता थे। बड़ी तादाद में महिलाओं की भागीदारी

पर अपना संतोष जताया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारियों की आँखें खोलने वाली है, जब भी महिला आरक्षण की बात की जाती है या महिलाओं की भागीदारी की बात आती है तो नाटक करते हैं।

राज्य सम्मेलन के अवसर पर महिला सशक्तिकरण पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका साथी जी. देवराजन न किया। फारवर्ड ब्लॉक केरल कमिटी की ओर से साथी वी. राम मोहन, महासचिव, साथी थंकचन वर्गीस, सचिव, के अलावा साथी अब्दुल कादेर वफाकला (इर्नाकुलम जिला सचिव और अध्यक्ष स्वागत कमिटी), साथी जैसन मंजली फारवर्ड ब्लॉक राज्य कमिटी सदस्य, साथी बैजु मेनाचरी, यूथ लीग राज्य कोषाध्यक्ष, साथी थाम्पी पुन्नाथला, फारवर्ड ब्लॉक कोल्लम जिला सचिव आदि ने भी प्रतिनिधि सत्र और सेमिनार को संबोधित किया।

सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी महिला संगठनों को राज्य महिला आयोग शामिल करने की मांग सरकार से की जायेगी। सभी महिला काउन्सिल का निर्माण किया जाये जो स्वयं रोजगार करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करेगा तथा देख-रेख करेगा। सम्मेलन में यह भी में यह भी मांग की गयी कि स्थानीय क्षेत्रों में महिला समूहों, कुदुम्बा श्री और अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं का राजनीतिकरण न किया जाये।

सम्मेलन में 21 सदस्यीय राज्य कमिटी का भी गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष - साथी शेरली (एर्नाकुलम), उपाध्यक्ष - साथी श्रीकला ब्रह्मानंदन (कोल्लम), महासचिव - साथी श्रीकुमारी अम्मा (तिरूवनंतपुरम), सचिव - साथी सुजाता थाम्पी (कोल्लम), कोषाध्यक्ष - साथी श्रीलता हरीन्द्रन (कन्नुर), राज्य सदस्य - साथी गीता उन्नी (कोल्लम), साथी डी. साठी बाई (कोल्लम), साथी (एडवोकेट) जीजा जेम्स कंदाथील (तिरूवनंतपुरम), साथी रती देवी डी. (पत्तनमथिट्टा), साथी शेरली रेमीन (कन्नूर), साथी सुबैदा हसन बाबा (एर्नाकुलम), साथी अनिता प्रताप (एर्नाकुलम), साथी शनी सुरेश (एर्नाकुलम) और साथी सारदम्बा (कोल्लम) से चयनित किये गये।

......केरल संवाददाता

पश्चिम बंगाल स्थानीय निकाय चुनाव में वाममोर्चे को एक और झटका:

परिणामों की राज्य कमिटी द्वारा समीक्षा और जन आंदोलन कार्यक्रमों की तैयारी

पश्चिम बंगाल में 81 सीटों पर निगम चुनाव 30 मई 2010 को संपन्न हुआ, जिसका परिणाम वाममोर्चे के लिये निराशाजनक रहा। नगर निगम की 81 सीटों में वाममोर्चे को मात्र 18 सीटें मिली, जबकि 27 सीटों पर विपक्षी तृणमूल को और 7 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुई। मजे की बात यह रही कि 25 सीटों पर किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, और 4 सीटों पर 'टाई' हो गया। साफतौर पर इससे यह प्रदर्शित होता है कि 2005 के चुनावों के परिणाम की तुलना में वाममोर्चे के वोट बैंक में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है।

ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में फारवर्ड ब्लॉक ने 2005 के चुनावों 55 सीटों की तुलना में 21 नगर पालिकाओं में 43 सीटों पर जीत हासिल की।

पूरे चुनाव परिणाम पर समीक्षा के लिये 6 जून 2010 को फारवर्ड ब्लॉक ने मीटिंग की। जिला नेताओं ने इस मीटिंग में भाग लिया और निष्कर्ष निकाला की यह चुनाव परिणामकोई पृथक नहीं है। इस प्रकार से वाममोर्चे को वोट बैंक का झटका 2008 के पंचायत से ही आरम्भ हो गया था, और यह हार 2009 के लोकसभा चुनाव तक जारी था। लोगों में वाममोर्चे पर से विश्वास की कमी को दर्शाया है, जो कि इसके सबसे बड़ी भागीदार सीपीआई(एम) की गलतियों और कार्यभार में कमी के कारण हुई है। लेकिन ऐसे समय में यह भी स्वतंत्र रूप से घोषित किया गया कि वाममोर्चे के साथ लम्बे समय से भागीदार फारवर्ड ब्लॉक भी इस अपराजय के लिये अपने उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकता है। पार्टी के लिये यह आवश्यक है कि जमीनी स्तर से संगठन को पुनर्गठित करें और पुन: इसे ऊर्जा प्रदान करें और इसी तरह से अपने जनसंगठन को मजबूत करे। राज्य पर सत्तासीन होने के लिये पूँजीपती वर्ग से संघर्ष करने व वाम एकता को मजबुत करने के लिये पार्टी ने कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की। इस संघर्ष को जनता के साथ मिलकर तथा जनता के लिये किया जायेगा।

राज्य कमिटी ने, दिनभर चली लम्बी चर्चा के बाद निम्नलिखित 4 - बिन्दुओं पर ईमानदारी पूर्वक तत्काल कार्यक्रमों का पालन करने का निर्णय लिया:

(1)मई और जून माह में जिला स्तरीय जनरल बोडी मीटिंग का आयोजन प्रत्येक जिलें में किया जायेगा, जिसमें राज्य सचिव मण्डल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे।

(2)जन संगठनों का सदस्यता अभियान पुनः चलाया जायेगा तथा इसे मजबूत किया जायेगा एवं अधिक से अधिक जन संपर्क स्थापित करने के लिये इनके सम्मेलन का आयोजन स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर का किया जायेगा।

(3)इन कार्यक्रमों के साथ-साथ पंचायत से लेकर नगर निगम स्तर तक भ्रष्टाचार और पक्षपात के विरुद्ध जन संघर्ष किया जायेगा।

(4)वाम एकता को हर गांव में मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया जायेगा तथा जिसका पालन लगातार ईमानदारी के साथ होगा।

इन कार्यक्रमों को तैयार करते समय, राज्य सचिव सदस्यों ने वाम मोर्चो के उद्देश्यों को दिलाते रहे, जो जन संघर्ष में प्रमुख औजार है। हमारा उद्देश्य जनता के साथ – जनता के लिये संघर्ष के रास्तों से भटक गये तो वाम मोर्चा के प्रति भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वाम मोर्चा वाम मोर्चा की सरकार से जुड़ा हुआ है और हम स्वयं नौकरशाही और शक्तिशाली नौकरशाही संस्कृति पर निर्भर है। इससे पार्टी का वर्ग चरित्र कमजोर होता है। लोग वाम मोर्चा में अपना विश्वास खोने लगते है, पुनरूत्थान के लिये हमें अपने पिछले उद्देश्यों पर वापिस आना होगा।

(पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी की रिपोर्ट पर आधारित)

फारवर्ड ब्लॉक स्थापना दिवस पर नेताजी के चित्रों की प्रदर्शनी

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के स्थापना दिवस पर 22 जून 2010 को वाराणसी के अस्सी घाट पर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा आजाद हिन्द फौज के दो सौ ऐतिहासिक चित्रों की प्रदर्शनी लगायी कयी। इसमें नेताजी के 17 अगस्त 1945 को खींचा गया अंतिम चित्र, 21 अक्तूबर 1943 को आजाद सरकार के गठन सरीखे चित्रों को लगाया गया। चित्रों के अवलोकन के लिए लोगों की भीड़ लगी थी।

प्रदर्शनी का उद्घाटन ऑल इण्डिया यूथ लीग के राष्ट्रीय महासचिव तथा फारवर्ड ब्लॉक केन्द्रीय कमिटी सदस्य साथी संजय भट्टाचार्य ने किया। प्रदर्शनी में ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक के नगर मंत्री रंजन मुखर्जी, आशा मुखर्जी, घश्याम गुप्त, अजय वणिक, तापस मल्लिक, डॉक्टर रमाशंकर शास्त्री, पुष्पाचक्रवर्ती, मोनिका विश्वास सहित अन्य लोग रहे।

देशबन्धु चित्तरंजन दास की पुण्य तिथि मनाई।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की वाराणसी नगर कमिटी के तत्वावधान में दशाश्वमेघ स्थिति चित्तरंजन पार्क में देश बंधु चित्तरंजन की 86वीं पुण्य तिथि मनायी गयी। इस मौके पर फारवर्ड ब्लॉक केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं ऑल इण्डिया यूथ लीग के राष्ट्रीय महासचिव साथी संजय भट्टाचार्य ने देशबन्धु जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि देशबन्धु चित्तरंजन महान त्यागी नेता थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिये पलभर में अपना सब कुछ त्याग कर दिया। वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, अपनी धर्मनिरपेक्ष सोच, जनवादी मूल्यों, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के नेता के रूप में हमेशा याद किये जायेंगे।